*भविष्य की बैंकिंग**

शक्तिकांत दास

बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग सम्मेलन में, इस विशिष्ट जनसमूह के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और सम्मेलन के विषय के रूप में 'भविष्य की बैंकिंग' (बैंकिंग बियोंड टुमॉरो) का चयन करने के लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बधाई देता हूँ। यह देखते हुए कि तीव्र गति से हो रहे नवोन्मेष, महत्वपूर्ण बदलावों और नए कारोबारी मॉडलों के उभरकर आने से बैंकिंग परिदृश्य दूरगामी परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है; मैं समझता हूँ कि इस विषय पर सक्रिय चर्चा करना समीचीन होगा।

आज मैं अपने सम्बोधन में वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति पर बात करूंगा और बैंकों द्वारा निभाई जा रही विशेष भूमिका तथा बैंकिंग क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों को रेखांकित करूंगा। मैं भविष्य की बैंकिंग के संभाव्य स्वरूप और उससे जुड़े अवसरों और चुनौतियों को भी रेखांकित करने का प्रयास करूंगा।

समष्टि आर्थिक परिस्थिति: आज हम कहाँ खड़े हैं

हम एक अस्थिर समय में जी रहे हैं। यूरोप में लगातार जारी युद्ध और महामारी ने वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया है। कई देश अनपेक्षित रूप से उच्च मुद्रास्फीति और खाद्य महंगाई, आपूर्ति शृंखला बाधाओं और उत्पाद एवं श्रम बाज़ारों में मांग-आपूर्ति असंतुलनों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक तेज गति से मौद्रिक नीति को सख्त बनाए जा रहे हैं, जिससे एक आसन्न मंदी का भय पैदा हो रहा है। वस्तुओं की कीमतों में जून की तुलना में गिरावट जरूर हुई हैं, पर अब भी ऊपर बनी हुई हैं। अमेरिका में उच्चतर ब्याज दरों और इसके साथ-साथ वैश्विक निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृति के कारण, सुरक्षित निवेश की मांग और अमेरीकी डॉलर की मजबूती तीव्र हो गई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई), यहाँ तक कि कुछेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की मुद्राएँ भी अमेरिकी डॉलर *के मुक़ाबले* कमजोर हो रही हैं। परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ रहे हैं और बाहरी स्रोतों से निधियाँ जुटाना महंगा होता जा रहा है, जिससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। समग्र रूप से देखें तो अस्थिर भू-राजनीतिक परिस्थिति के बीच वैश्विक परिदृश्य संकटपूर्ण बना हुआ है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को विघटित और खंडित करने वाली ताकतों को युद्ध और महामारी से शह मिल रही है।

ऐसे वातावरण में, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसका समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार मजबूत है। वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त पूंजी है, आस्ति गुणवत्ता संकेतक बेहतर हुए हैं, तुलनपत्र ज्यादा सुदृढ़ हैं, और बैंक लाभप्रदता की स्थिति में लौट आए हैं। ऋण-मांग में भी अच्छा सुधार हो रहा है। व्यापारिक आघातों और पूंजी के बाहर जाने से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए बाह्य क्षेत्र पर्याप्त रूप से निधिकृत है। आरबीआई की हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली आघातसह बनी हुई है और चल रही आर्थिक बहाली को समर्थन दे रही है। बैंक अपनी न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के स्तर से नीचे खिसके बिना ही गंभीर दबाव परिदृश्यों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। रिज़र्व बैंक प्रतिकूल चुनौतियों के प्रति लगातार सजग है और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सक्रियतापूर्वक कदम उठाने के लिए तत्पर रहेगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में हुई हालिया गतिविधियों से तीखी बहस छिड़ गई है और रुपये के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक गिर जाने के अंदाज लगाए जा रहे हैं क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो फंड भारत से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस मुद्दे के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए तथ्यपरक ढंग से अपनी बात रखना चाहूँगा।

सबसे पहले यह स्वीकारना जरूरी है कि मौद्रिक नीति में वैश्विक सख्ती के प्रसार-प्रभाव, भूराजनीतिक परिस्थिति, वस्तुओं- खासकर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि बनी रहना और महामारी के प्रभावों का लंबा खिंचते चले जाना- इन सभी के एक साथ आ जाने से, दुनिया के सभी देश अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि आरक्षित मुद्राएँ (रिज़र्व करेंसी) जैसे कि जापानी येन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी इससे अछूती नहीं रही हैं। पोर्टफोलियो फंड आस्तियां बेच रहे हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) पूंजी के

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जुलाई 2022 को मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में भाषण दिया गया।

बाहर जाने, मुद्रा अवमूल्यनों और रिज़र्व में गिरावटों से विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे इन देशों में समष्टि आर्थिक प्रबंधन जटिल हो गया है।

दूसरी बात, भारत पर इन भारी प्रसार-प्रभावों का असर अपेक्षाकृत कम पड़ा है। वस्तुतः, भारतीय रुपया अपने उन्नत और ईएमई समकक्षों की तुलना में बेहतर बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आधारभूत व्यवस्था सुदृढ़, आघातसह और अक्षुण्ण है। आर्थिक बहाली क्रमशः मजबूत हो रही है। चालू खाता घाटा अधिक नहीं है। मुद्रास्फीति स्थिर हो रही है। वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह पूंजीकृत और सुदृढ़ है। जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज अनुपात कम हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

तीसरी बात, इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि आयात और कर्ज चुकौती संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा पोर्टफोलियो बहिर्वाहों के कारण बाजार में मांग के मुक़ाबले विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वास्तव में कमी है, पर्याप्त विदेशी मुद्रा चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है। आखिरकार, यही वह उद्देश्य है जिसके लिए हमने विदेशी मुद्रा भंडार जमा किए थे, जब पूंजी के अंतर्वाह मजबूत थे। और, मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा, आप छाता इसलिए खरीदते हैं कि जब बारिश हो तो वह काम आए!

चौथे, बकाया ईसीबी के सर्वाधिक भाग को हानि से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी ढंग से बचाव-व्यवस्था की गई है। इसे मैं विस्तार से बताता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक की जून 2022 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया ईसीबी में से 44 फीसदी यानी 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए बचाव-व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रेलवे और बिजली क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की देयताएं शामिल हैं जिनके पास ऐसी आस्तियां हैं जो स्वाभाविक रूप से बचाव/ हेज करने की विशेषता रखती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में विदेशी मुद्रा जोखिम होने की स्थिति में सरकार द्वारा भार उठाया जा सकता है। ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। शेष 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी बकाया कुल ईसीबी का 22% है। इसमें भी उन कंपनियों के उधार शामिल हैं जिनके पास विदेशी मुद्राओं में प्राप्त होने वाली आय के रूप में स्वाभाविक हेजिंग है। इस प्रकार कुल बकाया ईसीबी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा वास्तव में बिना किसी सुरक्षा के (अनहेज्ड) है। कॉरपोरेट संस्थाओं को अंततः समझौताकारी तालमेल बैठाना पड़ता है क्योंकि एक ओर यदि कॉरपोरेट संस्थाएं अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को पूरी तरह से हेज करते हैं, तो उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा में सस्ते उधार लेने का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर, विनिमय दर दबाव में होने की स्थिति में उन्होंने जितनी राशि को हेज नहीं किया है उतनी ही ऋण चुकौती की राशि बढ़ जाती है। इसी कारण यथायोग्य हेज अनुपात की अवधारणा अस्तित्व में आई, जो हेजिंग के अनुपात की गणना करता है, जिससे पोर्टफोलियो में परिवर्तन कम होता है। हमारे आंतरिक शोध का अनुमान है कि भारत के लिए यथायोग्य हेज अनुपात 63 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए। स्वाभाविक हेजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, भारत के विदेशी ऋण में ईसीबी के स्टॉक के मामले में इष्टतम हेजिंग अनुपात को बनाए रखने की शर्त को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया है।

अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के उपायों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, रुपये का मूल्य अपेक्षाकृत सुचारू और व्यवस्थित रहा है। अचानक होने वाले और अस्थिर कर देने वाले बदलावों से बचते हुए, हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदें बरकरार रहें तथा विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर तरीके से काम करे और अर्थसुलभ बने रहे। विदेशी मुद्रा बाजार पर हमारा ध्यान बना रहेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रुपये का स्तर बुनियादी स्तर के अनुरूप हो। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हमारे मन में रुपये को लेकर कोई विशिष्ट स्तर नहीं है, लेकिन हम इस स्तर के उचित विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसकी अस्थिर चाल और तीव्र उतार-चढ़ाव हमें पूर्णतः अमान्य है।

बैंक विशेष संस्थाएं होती हैं- उनमें स्थायित्व अपेक्षित है

बैंक विशेष हैं और वे किसी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह नहीं हैं। वे केवल शेयरधारकों के हितों के संरक्षक नहीं हैं बल्कि मूल रूप से जमाकर्ताओं के विश्वास के संरक्षक अधिक हैं। बैंकिंग प्रणाली के केंद्र में जमाकर्ता होते हैं। देश में एक मजबूत, विश्वसनीय और स्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैंकों के लिए यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा नियोजित धन जमाकर्ताओं का है और यह उचित जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में परिलक्षित होना चाहिए।

बैंकों के संबंध में यहां भी अपेक्षा की जाती है कि विनियामकीय लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वे स्थायी संस्था बने रहें। वे सुदृढ़ विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रथाओं द्वारा शासित होती हैं। सुदृढ़ कार्यप्रणाली और जोखिम प्रबंधन, जो बैंक के कामकाज का अभिन्न अंग है, को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की होती है। पूंजी, चलनिधि और प्रावधानीकरण मानदंडों के संदर्भ में विनियामकीय निर्देशों से परे जाना और उनसे आगे जाना सुशासन और मजबूत जोखिम प्रबंधन का संकेत होगा। यह बैंकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें तनाव की स्थितियों के दौरान अपने स्वयं की बैलेंस शीट का सहारा लेने में सक्षम बनाएगा।

इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि जहां बैंकिंग के कारोबार में शेयरधारकों का हित महत्वपूर्ण है, वहीं जमाकर्ताओं का हित और भी महत्वपूर्ण है। बैंकों के शेयरधारकों को दीर्घावधि लाभप्रदता और बाजार मूल्यन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह निवेशकों को मध्यम से दीर्घावधि में सृजित होने वाले मूल्य के लिए बैंकिंग संस्था की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा। यह दृष्टिकोण बैंकिंग के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगा।

भविष्य के लिए बैंकों की तैयारी

बैंकिंग का बदलता परिदृश्य

बैंकिंग क्षेत्र मंथन के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में ग्राहकों की बैंकिंग उद्योग से अपेक्षाएँ बढ़ जाएँगी और बैंकों को ग्राहकों की पसंद और प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रत्येक बदलाव मौजूदा और नई संस्थाओं के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां पेश करेगा। यह ध्यान में रखना होगा कि कभी-कभी बदलाव इतने अचानक हो सकते हैं कि उनका अनुमान लगाना असंभव होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि 'भविष्य की बैंकिंग' (i) उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादों और सेवाओं के अनुकूलन, उन्नत व्यवसाय और प्रक्रिया स्वचालन और (ii) सुदृढ़ अभिशासन ढांचे, बेहतर सूचना प्रबंधन, काम करने के तरीके में बदलाव, आघातों को सहने की बढ़ी हुई क्षमताओं के निर्माण और बैंकों के लिए एक अधिक जिम्मेदार सामाजिक और पर्यावरणीय भूमिका के साथ उपयुक्त व्यवसाय मॉडल के विकास को प्राथमिकता देगी। मैं उपर्युक्त बातों को विस्तार से रखना चाहता हूँ।

डिजिटलीकरण में वृद्धि, व्यक्ति अनुकूल सेवाओं की पेशकश और फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम

बाजार संरचना और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम से अथवा स्व-उन्नयन के माध्यम से पारंपरिक बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में हुई वृद्धि ने नए जमाने के बैंकिंग के विचार को प्रतिध्वनित किया है। इससे अभिनव उत्पादों, सेवाओं और नए व्यापार मॉडल का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संदर्भ में, यह अक्सर कहा जाता है कि बैंकों को फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो पहले से ही वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज के ग्राहक, विशेष रूप से खुदरा ग्राहक, बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें त्वरित, विश्वसनीय और व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराएँ। इसलिए प्रासंगिक बने रहने के लिए, बैंकों को प्रभावी और समय पर व्यापार निर्णय लेने, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें व्यक्ति अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए नई और परीक्षण में उपयुक्त पाई गई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। भविष्य की बैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

मुक्त बैंकिंग (ओपन बैंकिंग)

वैश्विक स्तर पर देखें तो नई प्रौद्योगिकियों और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की उपलब्धता से बैंकिंग अधिक 'मुक्त' होती जा रही है जो बैंकों के साथ-साथ फिनटेक के बीच भी अंतर-संचालन की अनुमति देती है। इस आयाम ने ग्राहक अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक तेजी से और बेहतर रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक सहयोग हेतु अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराये हैं। अन्य विकसित देशों के विपरीत, भारत ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जहां विनियामक और बाजार, दोनों ने मिलकर ओपन बैंकिंग के विकास के लिए काम किया है। भारत में ओपन बैंकिंग की शुरुआत करने में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपीआई की सफलता, अकाउंट एग्रीगेटर (एए) संरचना के क्रियान्वयन और डिजिटल

बैंकिंग सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के साथ भारत में नए बिजनेस मॉडल का उदय हो रहा है। ग्राहकों को, अपनी सूचनाओं का बेहतर उपयोग करने और व्यापक तथा समृद्ध सेवा समूह का लाभ उठाने के लिए, सुविधा प्रदान करने हेतु कई बैंक नए युग के सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।

उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप, वेबसाइट नैविगेशन और उन्नत ग्राहक सेवा

नए तकनीक-प्रेमी ग्राहकों और बैंकिंग जगत में डिजिटलीकरण की लहर को देखते हुए, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे संचार के डिजिटल और कागज आधारित रूपों के बीच एक अच्छा संतुलन भी बनाएं। हालांकि बैंकों के ऐप्स और वेबसाइटों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, फिर भी ग्राहकों के लिए आसान नैविगेशन की सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। प्रकटीकरण और सूचनाओं तक पहुंच को सरल बनाने तथा वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करने में ग्राहकों को मदद करने के लिए चैटबॉट जैसी नवोन्मेषी सुविधा देने से बैंकिंग अनुभव में काफी वृद्धि होगी।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं और उसमें सतत सुधार भी हुए हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक में परिलक्षित होते हैं। वेतन भुगतान, सरकारी नकद अंतरण और घरेलू विप्रेषण जैसी डिजिटल भुगतान प्राप्तियां वित्तीय समावेशन अभियान में सहायक साबित हुई हैं। जनधन-आधार-मोबाइल त्रय (जेएएम ट्रिनिटी) की प्रेरणा के परिणामस्वरूप वंचित और अल्प सेवा प्राप्त लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकियां, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए बाधाओं को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका पेश कर रही हैं, फिर भी हमें उन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है जिनकी इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। पारंपरिक शाखा बैंकिंग में मानवीय संवाद अभी भी कई मायनों में ग्राहकों के लिए प्रासंगिक होगा। कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को समय पर और निर्बाध ऋण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। जहां आरबीआई अपने विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) के माध्यम से एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को ऋण देने की पहल को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है, वहीं अन्य हितधारक जैसे बैंक और फिनटेक कंपनियां भी लागत-प्रभावी और निर्बाध तरीके से डिजिटल क्रेडिट वितरण तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग कर रही हैं।

सोशल मीडिया और सूचना माध्यमों का उपयोग

सोशल मीडिया लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मंच है। भारतीय लोग औसतन प्रतिदिन लगभग 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया के उपयोग के विश्लेषण से बैंकों को अलग-अलग ग्राहक समूहों की पहचान करने, नए ग्राहक बनाने और वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया का उपयोग ग्राहक शिकायत निवारण प्रबंधन में भी किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा

डिजिटल बैंकिंग में प्रगति के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी। बैंकों द्वारा आईटी सिस्टम का बढ़ता उपयोग, दूरस्थ कार्य व्यवस्था, ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को त्वरित रूप से अपनाने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भरता बढ़ने से व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की वहनीय क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसमें साइबर हमलों के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करने, अक्षम करने या नष्ट करने या गोपनीय जानकारी और डेटा चोरी करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के खिलाफ मजबूत सुरक्षा का निर्माण करना शामिल है। बैंकों को अपने कर्मियों की क्षमता में निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। निरंतर ज्ञान अर्जन और समय से आगे रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

जलवायु संबंधी जोखिमों के संबंध में व्यापक और रणनीतिगत दृष्टिकोण

आने वाले समय में जलवायु संबंधी जोखिम एक प्रमुख जोखिम क्षेत्र होगा। इस तरह के जोखिम बैंकों की कारोबारी प्रणाली को प्रभावित करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यवसायों

[1] ग्लोबल वेब इंडेक्स सोशल मीडिया ट्रेंड्स 2019 रिपोर्ट।

और उद्योग को वित्त पोषण की बढ़ी हुई आवश्यकताएं, जलवायु संबंधी जोखिम प्रबंधन पर उठाए गए वैश्विक परिवर्तनों से काफी प्रभावित होंगी। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय विभिन्न हितधारक पहले से ही पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। वैश्विक जलवायु के प्रति स्थिरता बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तपोषण वाली आस्तियों के मूल्यांकन सहित बैंक अपने व्यवसायों को तेजी से इनके अनुरूप बना रहे हैं। बैंकों को उचित व्यावसायिक कार्यनीति विकसित करने और संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए आभिशासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए एक दूरदर्शी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता होगी।

समग्र रूप से

आने वाले समय में उम्मीद है कि बैंकिंग की दुनिया अधिक परस्पर सहयोगी होने के साथ-साथ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगी, जिसमें नए भागीदार होंगे जो नवीन वित्तीय उत्पादों की पेशकश लेकर आएंगे। बैंकों को उचित व्यवसाय मॉडल, संवहनीयता, स्थिरता और उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए इस गतिशील वातावरण का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित अभिशासन सफलता का मूल है और इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों को डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराधों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंततः, बैंकिंग एक सेवा है, और बेहतर ग्राहक सुरक्षा और अनुभव को वह प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। विनियामक की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, नए परिवर्तनकारी नवोन्मेषों को स्थायी तरीके से समायोजित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतिहास गवाह है कि जब-जब प्रौद्योगिकी, बाजार सहभागियों और विनियामकों ने हाथ मिलाया है, तब-तब क्रांतिकारी नवोन्मेष और संवृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल के हमारे बैंक इसे साकार करेंगे।

धन्यवाद।